फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 261 प्रभात जयपुर, मंगलवार 23 अप्रेल, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

Colonial ambition drove mountaineers to Himalayas

Richard Bass made it to the summit led by his climbing partner. It ushered in a new era of 'commercialisation,' the idea that anyone could climb the Everest for a fee gained currency.

Coffee's prehistoric origin is older than homo sapiens

बेटे के लिए जालोर-सिरोही में हर घर का दरवाजा खटखटाया गहलोत ने

पर आम लोगों में पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति बड़ी फीकी प्रतिक्रिया देखी गई

- **मुस्लिम मुसाफिर खाने में हुई मुस्लिम समाज की बैठक में भी आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रहना चर्चा का विषय बन गया है।**
- **प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद वैभव गहलोत की स्थिति और ज्यादा खराब बताई जा रही है। यही कारण है कि, गहलोत घर-घर जा रहे हैं, पर जनता में उनके प्रति कोई उत्साह नहीं दिख रहा है।**

जालोर, 22 अप्रेल (कासं)। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नाक का सवाल बनी जालोर- सिरोही लोकसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। साथ ही, उनके कई नज़दीकी नेता व मंत्री भी कई दिनों से जालोर में डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने बेटे वैभव की सीट बचाने के लिए डोर टु डोर सम्पर्क किया। इस दौरान जनता में उनके प्रति क्रेज़ बहुत कम नज़र आया। इसके अलावा मुस्लिम मुसाफिर खाने में हुई मुस्लिम समाज की बैठक में लोगों की संख्या भी कम थी।

जालोर-सिरोही लोकसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इसलिए उनका पूरा ध्यान केवल जालोर-सिरोही सीट पर केन्द्रित है। छोटी - छोटी बैठकें लेने के बाद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालोर शहर के हरिदेव जोशी सर्किल पर डोर टु डोर सम्पर्क कर दुकानदारों से अपने बेटे के लिए मत व समर्थन मांगा। लेकिन इस दौरान लोगों का उत्साह कम नजर आया। जब वे मुख्यमंत्री थे, तब लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कतारों में खड़े होते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि, वे अपने बेटे के लिए एक एक कार्यकर्ता से हाथ मिलाकर वोट व समर्थन मांग रहे हैं।

जालोर में मुस्लिम मुसाफिर खाने में मुस्लिम समाज की एक बैठक रखी गई जिसमें बहुत कम संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। जिसके लिए कहा जा रहा है कि, लोगों को इसकी सूचना नहीं मिली। बैठक में काफी कुर्सियां खाली रहना भी चर्चा का विषय बना रहा। मुस्लिम समाज के कई लोगों ने यह कहकर रोष भी प्रकट किया कि, उन्हें बुलाया नहीं गया।

पूर्व मु.मंत्री जालोर- सिरोही क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाने का मानस भी नहीं बना रहे हैं।

वे जालोर- सिरोही से लगी सीटों, पाली व बाडमेर तथा उदयपुर से आगे दौरे नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान किसी प्रकार से अपने बेटे को जिताने पर केन्द्रित है। इसके लिए उनके नजदीकी नेता, संयम लोढा, गोविन्द राम मेघवाल, टीकाराम जूली, मदन प्रजापत सहित कई पूर्व मंत्री व नेताओं ने जालोर में डेरा डाला हुआ है।

कई टीमें वैभव गहलोत के लिए समर्थन मांगने में जुटी हुई हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि, प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद पूर्व मु.मंत्री को ऐसा लग रहा है कि, इस सीट को निकालना मुश्किल है। इसलिए वे अब खुद मैदान में उतर कर डोर टु डोर सम्पर्क करने में जुटे हुए हैं और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं।

प्र.मंत्री मोदी आज टोंक में

टोंक, 22 अप्रेल (निसं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टोंक-सवाईमाधोपुर क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के समर्थन में मंगलवार को उपखण्ड उनियारा में जनसभा को सम्बोधित करेंगे।

इस संदर्भ में सोमवार को भाजपा के नेता राजेन्द्र राठौड़ मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष के मीडिया कार्यालय में प्रेस से मिले। उन्होंने कहा कि, टोंक जिले के उनियारा उपखण्ड में प्रधानमंत्री मोदी की पहली सभा है, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं और आमजन के पहुंचने की सम्भावना है।

राठौड़ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में

- **प्रधानमंत्री उनियारा में भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे।**

जितनी भी योजनाएं चालू की गई हैं, उनसे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। आज पूरा देश मोदी की गारन्टी पर ही विश्वास करता है।

राठौड़ ने यह भी कहा कि, जिस संविधान को बाबा साहेब ने बनाया है उसको छेड़छाड़ करने की हमारी कोई नीयत नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी उन्होंने पुत्र मोह का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि, मतदान के प्रथम चरण में गत 19 अप्रेल को मतदान का प्रतिशत कम रहने का कारण तेज गर्मी तथा बड़ी संख्या में विवाह समारोह आदि थे।

उन्होंने अन्त में कहा कि, देश में मोदी का मैजिक कायम है और कायम रहेगा।

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी, जिसने गुजरात में वर्ष 2019 में सम्पन्न लोक सभा चुनावों के दौरान सभी 26 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की थी, उसने इस बार के चुनावों में पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल के सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने के साथ ही अपना खाता खोल दिया है। क्योंकि

- **सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया और शेष ने अपना नाम वापस ले लिया।**

इस सीट से अन्य सभी उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं।

कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी निलेश खुम्मानी का नामांकन इसलिए खारिज हो गया क्योंकि उनके प्रस्तावक ने अपना नाम नामांकन से वापस ले लिया था और शेष 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए इस के बाद चुनाव आयोग ने एक मात्र उम्मीदवार रहे दलाल को निर्विरोध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'प्रधानमंत्री मोदी ''इस्लामोफोबिया'' फैला रहे हैं'

कांग्रेस ने मोदी के भाषणों को नफरत फैलाने वाला बताकर चुनाव आयोग से एक्शन लेने को कहा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर, हाल ही में बांसवाड़ा और अलीगढ़ में हुई चुनावी सभाओं में ''इस्लामोफोबिया'' (मुसलमानों के प्रति भय व घृणा) फैलाने का आरोप लगाया है। इन टिप्पणियों के आधार पर विपक्षी दल कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर उनके विरूद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है।

दूसरे चरण का मतदान होने को हैं, और भाजपा के नेताओं ने स्पष्ट रूप से चुनावी रणनीति बदल दी है। तथा ऐसा प्रतीत होता है कि, सीधे ही मूल हिन्दु मतदाताओं को सम्बोधित करना शुरू कर दिया है। पूर्व में, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के लिए कहा था कि, ''लगता है कि यह भारत के विभाजन से पूर्व मुस्लिम लीग द्वारा तैयार किया गया घोषणा पत्र है।''

कल, बांसवाड़ा की एक आम सभा में उन्होंने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया, जब उन्होंने कहा कि, कांग्रेस की, संपत्तियों की पुनर्वितरण योजना लागू होने से अल्पसंख्यकों और अवैध घुसपैठियों को लाभ होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि, यदि कांग्रेस को वोट देकर सत्ता में लाया गाया तो वो देश की सम्पत्तियों को उन लोगों को दे देगी ''जिनके ज्यादा बच्चे हैं।''

प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अपने भाषण में कहा था कि, अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों का राज्य के संसाधनों पर प्रथम अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने जवाब में कहा कि, मनमोहन सिंह ने भाषण में दलितों, महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्गो एवं दबे-कुचले लोगों के बारे में यह बात कही थी, सिर्फ मुस्लिमों के बारे में नहीं। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री की उक्त टिप्पणियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है।

कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात का समय मांगा है ताकि वे उन्हें, ''अपनी पार्टी के घोषणापत्र के बारे में समझा सकें।'' मोदी की टिप्पणियों को उन्होने

- **दूसरे चरण के मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी बताया है, उसकी भारी आलोचना हो रही है।**
- **कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी मुझे समय दें, मैं उन्हें कांग्रेस का घोषणा पत्र समझाना चाहता हूँ।**
- **सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से इस बयान के लिए प्रधानमंत्री पर कार्यवाही की मांग की। चुनाव आयोग फिलहाल मौन है पर 1987 में इस तरह की भाषण बाजी पर चुनाव आयोग ने शिवसेना नेता बाल ठाकरे पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया था।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आंध्र प्रदेश में भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

-नई दिल्ली, 22 अप्रेल। खण्डित आंध्रप्रदेश के कोनसीमा जिले के वोटर्स से बातचीत करने के बाद यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि मुख्यमंत्री एवं युवजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी (वाय.एस.आर.सी.पी.) के प्रमुख वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी तेलुगू देसम पार्टी (टी.डी.पी.) द्वारा प्रस्तुत साहसपूर्ण चुनौती से कठिन परिश्रम के बाद पार पा लेंगे। टी.डी.पी. का भाजपा के साथ चुनावी गठबंधन है और वह अब एन.डी.ए. का हिस्सा है।

आंध्रप्रदेश उन दो राज्यों में से एक है जहां लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। वृद्ध हो चुके टी.डी.पी. सुप्रीमो एन. चन्द्रबाबू नायडू के लिए राज्य में सत्ता में आने का यह शायद आखिरी मौका भी है।

हालांकि, यहां जगन विरोधी मनोभाव सुस्पष्ट हैं तथा राज्य सरकार के विरुद्ध सत्ता विरोधी लहर भी हैं, लेकिन इसके साथ यह बात भी है कि जगन पांच साल पहले जबसे सत्ता में आए हैं, तब से ही यहां के स्थानीय निवासी पर वास्तव में राज्य के लोग उनकी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं। आंध्र का ऐसा एक भी मतदाता नहीं है जो उनकी कल्याणीकारी योजनाओं और धन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से लाभांवित ना हुआ हो। चाहे वह एस.सी. हो, एस.टी. हो, महिला, छात्र, किसान या श्रमिक हो। उसे सरकार से कुछ ना कुछ अवश्य मिलता रहा है। मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि वर्ग, जाति और पंथ पर ही केन्द्रित ना रहकर समाज के विभिन्न वर्गों में कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त उपहारों का प्रभावी वितरण हो। उदाहरण के तौर पर गरीब व वंचित वर्ग के प्रत्येक बच्चे को वित्तीय सहायता देने के लिए अम्मा वॉयड, प्रत्येक पंजीकृत वकील को पांच हजार रूपए, ऑटोरिक्शा चालकों की पेंशन और सहायता के लिए वाहन मित्र। कोनसीमा के जिला मुख्यालय अमालापौरम के एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि ''जगन मोहन ने वर्ष 2019 में जब से विधानसभा चुनाव जीता, वह तभी से अपने पुनर्निर्वाचन के जतन करते रहे हैं।

- **राज्य की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और तेलुगुदेशम, में सत्ता के साथ-साथ भाजपा का सान्निध्य पाने की भी होड़ लगी है।**
- **मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के सामने सरकार विरोधी लहर की कड़ी चुनौती है, पर अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं व खुले हाथों से हर वर्ग को तोहफे देने की नीति से उन्हें चुनाव जीतने की उम्मीद है।**
- **तेलुगुदेशम पार्टी राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को जोर-शोर से उठाकर अपनी नैया पार लगाना चाहती है। यही नहीं, वह एन.डी.ए. का हिस्सा भी है।**
- **स्थिति यह है कि, राज्य में चन्द्र बाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी में से कोई भी जीते, दोनों ही दल भाजपा को केन्द्र में समर्थन देने को आतुर हैं।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विदेशी राजनयिकों का दल जोधपुर में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रेल। विभिन्न मिशनों के राजनयिकों का एक सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारत में राजस्थान के जोधपुर में आया है जो वर्तमान लोकसभा चुनाव के चलते वह यहां 22 अप्रेल से 24 अप्रेल तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित चुनाव अभियान का अनुभव लेगा और

- **भाजपा का चुनाव अभियान देखने आई यह टीम 22 से 24 अप्रैल तक जोधपुर में रहेगी।**

प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करेगा।

इस राजनयिक प्रतिनिधिमंडल में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, रुस व सूरीनाम के राजनयिक शामिल हैं।

इससे पूर्व, ऐसा ही एक प्रतिनिधिमंडल भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का अनुभव लेने वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश व गुजरात विधानसभा के चुनावों के समय आया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 26000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नियुक्तियाँ रद्द कीं

हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के मद्देनज़र यह फैसला सुनाया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 26 हजार प्राथमिक स्कूल टीचर्स को बर्खास्त करने का आज आदेश दिया। इन टीचर्स की तृणमूल सरकार के वैस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने नियुक्ति की थी।

जैसे कि, तृणमूल कांग्रेस सरकार और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के दु:खों का कोई अंत ही ना हो, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व जज अभिजीत गांगुली द्वारा दिए गए आदेश की आज पुष्टि कर दी। कोर्ट ने 26 हजार से अधिक टीचर्स की नियुक्ति को रद्द करते हुए जस्टिस गांगुली के आदेश को यथावत रखा। इन टीचर्स की भर्ती परीक्षा और भर्ती की पूर्ण प्रक्रिया द वैस्ट बंगाल स्कूल सर्विसेस कमीशन ने संचालित की थी। इस प्रक्रिया को एक प्रत्याशी, जिसे नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया था, ने कोर्ट में चुनौती दी थी।

यह पाया गया कि स्कूल सर्विस कमीशन ने ब्लैक लिस्टेड शैडो कम्पनियों के जरिए भर्ती की एक अस्पष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया था। जस्टिस गांगुली के समक्ष रखीं गईं प्रथम दृष्टया जांच रिपोर्टों से गंभीर अनियमितताओं का पता चला था, जैसे कि अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया, जबकि एस.एस.सी. परीक्षा में कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी गई।

यह ''धन के बदले नौकरी'' का घोटाला था और चयन प्रक्रिया में शामिल लोगों ने पात्र की जगह अपात्र को नियुक्ति देने के लिए रिश्वत ली थी।

- **ये नियुक्तियाँ स्कूल सर्विस कमीशन ने की थीं। आरोप है कि, ये नियुक्तियाँ ''जॉब्स फॉर कैश'' के आधार पर हुई थी और प्राथमिक जांच के आधार पर पूर्व जज जस्टिस गांगुली ने इन्हें रद्द कर दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जस्टिस गांगुली के फैसले को कायम रखा।**
- **नियुक्तियों में भारी भ्रष्टाचार के कारण जस्टिस गांगुली ने सी.बी.आई. जांच के आदेश दिए थे। सी.बी.आई. टीम की रेड के दौरान शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी के घर करोड़ों रूपए मिले थे। उसके बाद से पार्थो चटर्जी जेल में हैं।**
- **कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले का चुनावों में तृणमूल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस फैसले ने तृणमूल के प्रति जनता का विरोध और बढ़ा दिया है।**

प्राथमिक खुलासों के आधार पर जस्टिस गांगुली ने सी.बी.आई. को इस मामले की पूर्ण जांच-पड़ताल करने के निर्देश दिए थे। जांच कार्रवाई के दौरान सी.बी.आई. शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर भी पहुंची थी और उनके एक आवास से नकदी बरामद की गई थी।

उसके बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। अब वह अपनी एक महिला मित्र के साथ राज्य की एक जेल में हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने स्वयं की इस गोरख धंधे से दूरी बनाते हुए अपयश के भागी अपने मंत्री को तुरंत पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

इसके बावजूद, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन अनियमितताओं का यह करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था कि जिन टीचर्स को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है उन्हें बर्खास्त ना किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि पात्र अभ्यर्थी बिना किसी नौकरी के परेशान होते रहेंगे। नियुक्ति ना पा सकने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पिछले दो वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

चुनाव प्रक्रिया के बीच में सुनाए गए इस निर्णय और उसके बाद राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया की भारी आलोचना से जनता के बीच सरकार की छवि खराब होगी, लेकिन ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया में उन अभ्यर्थियों को आश्वस्त करने की कोशिश की, जिन्हें अब बर्खास्त किया जा चुका है।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी सरकार इस संकट से कैसे निबटेगी। सरकार द्वारा नियुक्त टीचर्स अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठते हैं, और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल की रिहाई की याचिका खारिज

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को उनके विरूद्ध दर्ज सभी आपराधिक

- **दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75,000 रू. का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने सभी अपराधिक केसों में केजरीवाल को जमानत देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, वो भी केजरीवाल से बिना पूछे।**

केसों में एक असाधारण अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका दायर करने वाले पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)